अलका पाण्डेय

धरती बचाने की जरूरत

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार करने की दिशा में जल जीवन मिशन पर करीब 1.75 लाख ग्राम सभाओं के 62 लाख से ज्यादा लोगों से 2 अक्टूबर 2021 को चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने पानी पर सब के समान अधिकार, जल संरक्षण और उसका सही उपयोग करने के मुद्दों पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसको अपनाने से गांव अपनी पानी की आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'' सिद्धांत के अनुरूप इस मिशन का उदेश्य है कि ''कोई भी छूट न पावे'' और गांव के हर परिवार को नल से पानी का कनेक्शन मिल जाए।

21वीं सदी हमारी हो यह सपना सभी भारतीयों के दिल में है। लेकिन उसका मार्ग क्या हो? इस पर विचार करने की जरूरत है। विश्व की परिस्थिति देखते हुए यही कहा जा सकता है कि उसका मार्ग केवल एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। 12 मई 2020 को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को आह्वान करते हुए कहा था कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। उसका व्यापक असर लोगों पर पड़ा।

जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है तो इसका सीधा संबंध आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो किसी देश को उन्नति के शिखर तक ले जा सकती है। देश के नागरिकों में आत्मविश्वास तभी आएगा जब उनको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों। हमारे प्रधानमंत्री इसी विजन पर काम कर रहे हैं। महाभारत में एक जगह कहा गया है- अतिपरिचयात् अवज्ञा भवति अर्थात सहजता से उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के वास्तविक मूल्य का अनुमान हम आसानी से नहीं लगा पाते, भले ही वे जीवन के लिए कितनी ही उपयोगी क्यों न हों। पानी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पृथ्वी की सतह का दो तिहाई से भी अधिक भाग पानी से आच्छादित है। इसलिए हमको लगता है कि जब चारों तरफ पानी ही पानी है, तो फिर चिंता किस बात की? ऐसे में हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल पानी में से केवल दो प्रतिशत से भी कम मनुष्य के उपयोग लायक है। पहले पुराने तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़, और झील अपने अंदर बरसात के पानी को तो सहेजते ही थे साथ ही उनमें संचित जल धीरे-धीरे धरती के अंदर जाकर भूगर्भीय जल के स्तर को भी कम नहीं होने देते थे। लेकिन दुर्भाग्य से विकास की आधुनिक अवधारणा ने इस सच को अनदेखा कर दिया और इन तालाबों की जमीनों को ही पाट दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के 91 जलाशयों में केवल 20% ही पानी बचा है। जलवायु परिवर्तन से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। भूमिगत जलस्तर औसतन हर साल 1 फीट की दर से नीचे जा रहा है। हालांकि सरकार इसके लिए चिंतित और प्रयत्नशील है। इसके लिए सरकार ने जल समिति का गठन किया है। जिसके अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। इन जल समितियों में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इससे जल प्रबंधन अभियान में मजबूती आएगी। हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब जल की उपलब्धता बढ़ेगी।

जल जीवन मिशन की तैयारी

ग्राम पंचायत या उसकी उपसमितियां जल शुद्धिकरण, जल संरक्षण आदि की व्यवस्था करती हैं। देश में 6.05 लाख गांवों में से 3.03 लाख से ज्यादा गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियां बनाई जा चुकी हैं। इसमें स्थानीय ग्रामीण समुदाय गांव में ही जल व्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज का सपना साकार करने की दिशा में जल जीवन मिशन पर करीब 1.75 लाख ग्राम सभाओं के 62 लाख से ज्यादा लोगों से 2 अक्टूबर

2021 को चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने पानी पर सब के समान अधिकार, जल संरक्षण और उसका सही उपयोग करने के मुद्दों पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसको अपनाने से गांव अपनी पानी की आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'' सिद्धांत के अनुरूप इस मिशन का उदेश्य है कि ''कोई भी छूट न पावे'' और गांव के हर परिवार को नल से पानी का कनेक्शन मिल जाए। जिन गांवों में अच्छी गुणवत्ता वाला भूजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा उनमें एकल गांव योजनाएं तैयार करके उन्हें लागू करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए पानी की कमी वाले इलाकों में अन्य स्थानों से पानी लाने, जल उपचार संयंत्र लगाने और वितरण प्रणाली बनाने की योजनाएं लागू की जा रही हैं। कहीं-कहीं पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल उपलब्ध होने के बावजूद अच्छी गुणवत्ता नहीं होने के कारण गांव के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए गांव में घरों तक पानी सप्लाई करने से पहले उसे उपचारित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था अलग-अलग जनजाति बस्तियों/पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों के लिए की जाएगी।

हर गांव को जल प्रदान करने के लिए भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना।

जल जीवन मिशन के लिए कुल 3.60 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इसके अतिरिक्त 2.08 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जल संबंधी कार्यों के लिए उपलब्ध होगी। जल जीवन मिशन हर गांव को पानी, स्वच्छता और साफ सफाई की दृष्टि से लोगों को जागरूक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर गांव में वहां के पानी की उपयोगिता की देखरेख और प्रबंधन के वास्ते 25-30 लोगों का समूह बनाया जा रहा है। ऐसे प्रत्येक समूह में ग्राम जल स्वच्छता समिति के 10-15 सदस्यों के अलावा कम से कम पांच कुशल कारीगर रहेंगे जिनमें एक राजमिस्त्री, एक प्लंबर, एक इलेक्ट्रिशियन और एक पंप ऑपरेटर होगा। इस तरह जल मिशन के तहत गांव में पानी की सुविधाओं के प्रबंधन के लिए कुशल कारीगरों का एक विशाल पूल तैयार हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ने ग्राम सभाओं के लिए 2, अक्टूबर, 2021 के राष्ट्रव्यापी संबोधन में ग्रामीण समुदायों से आग्रह किया कि वे जल प्रबंधन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें ताकि किसी भी गांव को टैंकरों और रेलगाड़ियों से पानी मंगाने की जरूरत न पड़े। ऐसा सभी ग्राम वासियों के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। इससे एक अन्य बड़ा लाभ यह होगा कि ग्रामीण महिलाओं को पानी लाने के लिए काफी दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर वह अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल अन्य कार्यों में कर सकेंगी।

15, अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा किए जाने के समय सिर्फ 3.23 करोड़ घरों में ही पानी के

प्रधानमंत्री ने ग्राम सभाओं के लिए 2, अक्टूबर, 2021 के राष्ट्रव्यापी संबोधन में ग्रामीण समुदायों से आग्रह किया कि वे जल प्रबंधन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें ताकि किसी भी गांव को टैंकरों और रेलगाड़ियों से पानी मंगाने की जरूरत न पड़े।

लिए नल का कनेक्शन था। इसके बाद से 5.22 करोड़ कनेक्शन और दिए जा चुके हैं। इससे महिलाओं को दूर जाकर पानी लाने के झंझट से छुटकारा मिल गया। ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के सदस्यों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में किसी भी महिला को पानी लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अनुरोध किया कि वे अपने गांव में आवश्यकता और मांग से अधिक पानी का बन्दोबस्त करने का हर संभव प्रयास करें। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं का जीवन आसान हो जाने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अभी तक 7. 39 लाख से अधिक महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट की मदद से पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर गांव में 5% महिलाओं का समूह बनाया गया है। यह समूह घरों में लगे नलों के जल की गुणवत्ता परखने और उस पर लगातार निगाह रखने का काम करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल जनित बीमारियों और संक्रमण से छुटकारा पाया जा सकेगा। जल जीवन मिशन में ही एक उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति गांव में जल कनेक्शन देने के लिए स्थापित होने वाली जल आपूर्ति प्रणाली की पूरी रूपरेखा तैयार करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने सितंबर, 2020 में हर स्कूल (जनजाति बच्चों के रिहायशी स्कूल), आंगनवाड़ी केन्द्र और आश्रमशाला में पानी के नल कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु 100 दिन का जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 2, अक्टूबर 2020 को यह सुनिश्चित करने का अभियान शुरू किया कि स्कूलों, आंगनवाड़ी और आश्रम शालाओं सहित सभी शिक्षण केंद्रों में पीने के साफ पानी के लिए नल कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। इस कार्य के लिए हर राज्य अपने स्तर पर प्रयत्नशील है। इस समय 8.15 लाख (79.2%) स्कूल और 8.15 लाख (73%) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से पानी की सप्लाई हो रही है।

पर्यावरण की मार

पर्यावरण पर आई रिपोर्टें बताती हैं कि विश्व की एक तिहाई कृषि भूमि नष्ट

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का देश के नागरिकों से जल संरक्षण का आह्वान।

हो चुकी है, जबकि 87% प्राकृतिक आर्द्रभूमि गायब हो चुकी है। जलवायु परिवर्तन ने विश्व में बाढ़, अकाल और असाधारण गर्मी के प्रकोप जैसी विभीषिकाओं को जन्म दिया है जिनके कारण न केवल करोड़ों लोग मारे गए या विस्थापित हुए हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अरबों-खरबों डालर का नुकसान उठाना पड़ा है। गर्मी के मौसम आते ही देश के अलग-अलग हिस्सों से जल संकट की खबरें सामने आने लगती हैं। हर साल ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान का कोटा शहर इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह शहर चंबल नदी के किनारे बसा है। लेकिन इस शहर की अनेक बस्तियों में पानी की किल्लत रहती है। स्थिति यह है कि कई बस्तियों में तो नलों से बूंद-बूंद टपकने वाले पानी के लिए लोगों को रात-रात भर जागना पड़ता है। दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो पीने का पानी खोजने में अपना पूरा दिन लगाते हैं। फिर भी, जिन लोगों के पास सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, वे इसे हल्के में लेते हैं और इसका बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करते हैं।

'वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर' दुनिया के अग्रणी पर्यावरण संरक्षण संगठनों में से एक है जिसका मिशन प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना और प्रकृति तथा मनुष्यों के बीच सामंजस्य बनाना है। इस संगठन की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसने अपना पहला कार्यालय स्विस शहर मोर्गेस में खोला और स्विस कानून के तहत पंजीकृत है। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में इसके कार्यालय हैं और इसमें लगभग 6000 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पूर्णकालिक कर्मचारियों के अलावा, इसे विश्व स्तर पर लगभग 5 मिलियन सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त है। इसके अनुसार, दुनिया भर में लगभग 1.1 बिलियन लोगों के पास पानी की पहुंच नहीं है और कुल 2.7 बिलियन लोगों को वर्ष में कम से कम एक महीने के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। आज भी पूरी दुनिया में ऐसे कई दूरदराज के इलाके हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं क्योंकि वे कहीं भी पानी के करीब नहीं हैं। वे क्षेत्र जिन्हें मरुस्थल माना जाता है, या जो क्षेत्र एकांत में हैं, उनके पास जल के कुछ स्रोत नहीं होते हैं जहाँ लोगों को प्रभावी ढंग से पानी मिल सके। पूरी दुनिया में बढ़ता वायु और जल प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। ऐसा अनुमान है कि वायु प्रदूषण के कारण हर साल 70 लाख लोग असमय मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। विश्व में हर नौ में से एक मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण होती है। हर दस में से नौ लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। लेकिन दुनिया के केवल 57% देशों ने वायु प्रदूषण को कानूनी रूप से परिभाषित किया है। नवीनतम शोध बताते हैं कि दुनिया में तीन अरब से ज्यादा लोग केवल इस कारण स्वास्थ्य खतरों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भूमिगत जल की गुणवत्ता और इसके महत्व की जानकारी नहीं है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में डाले जाने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा वर्ष 2040 तक तीन करोड़ 70 लाख टन हो जाएगी। समुद्रों में बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण ने वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग, मत्स्य उद्योग एवं कृषि को केवल 2018 में उन्नीस अरब डालर का अनुमानित नुकसान पहुंचाया है।

प्राकृतिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

शुद्ध पानी की प्रयोगशाला की जरूरत

विज्ञान ने हमें भले ही उन्नति के नए सोपान सौंपे हैं, लेकिन आज तक दुनिया की किसी प्रयोगशाला में मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने लायक पानी नहीं बनाया जा सका है। इजराइल जैसे देशों ने समुद्री पानी को पीने के योग्य बनाने का दावा किया है, लेकिन उनकी तकनीक इतनी महंगी है कि वह लोकप्रिय नहीं हो पायी। हमारे पूर्वज जानते थे कि पानी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके संरक्षण की जरा-सी भी लापरवाही पीढ़ियों के अस्तित्व को संकट की ओर धकेल सकती है। इसलिए प्राचीन भारतीय मान्यताओं में किसी जल स्रोत के निर्माण को बहुत पुण्यदायी माना गया है।

दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तरह, भारत में भी सभ्यता नदियों और

डेल्टाओं के आसपास विकसित हुई। नदियाँ राष्ट्रीय संस्कृति की स्थायी प्रतीक होती हैं। हड़प्पा (या सिंधु घाटी) सभ्यता लगभग 5000 साल पहले विकसित हुई थी, जिसमें सुनियोजित शहर थे। सार्वजनिक और निजी स्नानागार, ठीक से बिछाई गई ईंटों से निर्मित भूमिगत नालियों के माध्यम से सीवरेज सिस्टम का एक सुनियोजित नेटवर्क था और इसके कई जलाशयों

विज्ञान ने हमें भले ही उन्नति के नए सोपान सौंपे हैं, लेकिन आज तक दुनिया की किसी प्रयोगशाला में मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने लायक पानी नहीं बनाया जा सका है। इजराइल जैसे देशों ने समुद्री पानी को पीने के योग्य बनाने का दावा किया है, लेकिन उनकी तकनीक इतनी महंगी है कि वह लोकप्रिय नहीं हो पायी। हमारे पूर्वज जानते थे कि पानी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके संरक्षण की जरा-सी भी लापरवाही पीढ़ियों के अस्तित्व को संकट की ओर धकेल सकती है। इसलिए प्राचीन भारतीय मान्यताओं में किसी जल स्रोत के निर्माण को बहुत पुण्यदायी माना गया है।

सिंधु घाटी सभ्यता में जल संसाधनों का चित्रण।

और कुओं के पास एक कुशल जल प्रबंधन प्रणाली थी। सभी प्राचीन सभ्यताएँ, जैसे हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और मिनोअन, जो फली-फूली और अपने शिखर पर पहुँची, वे काफी हद तक जल प्रौद्योगिकियों में अपनी प्रगति पर निर्भर थीं। जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के जरिए, वे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने और सूखे तथा बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम थी। साथ ही, उन्नत अपशिष्ट जल प्रबंधन तकनीकों ने स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण में मदद की। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जल तकनीकें अपने चरम पर थीं। समकालीन दुनिया में जल आपूर्ति और अपशिष्ट निपटान प्रणाली से संबंधित इतनी परिष्कृत और प्रभावशाली योजना कहीं नहीं मिल सकती है। लगभग सभी घरों में स्नान और शौचालय के साथ निजी कुएं थे, जो मानक आकार की पकाई हुई ईंटों द्वारा पंक्तिबद्ध थे।

निष्कर्ष

सारी भयावह परिस्थितियां एक ही निष्कर्ष की ओर संकेत कर रही हैं और वह यह कि, हमने अपनी आर्थिक समृद्धि पर्यावरण के विनाश की कीमत पर हासिल की है। नष्ट होते पारिस्थितिक तंत्रों ने महिलाओं, स्थानीय देशज समुदायों और हाशिये पर स्थित समूहों पर विनाशक प्रभाव डाला है। यदि हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के विनाश पर रोक लगा दें और इसके साथ ही परिवर्तित भूमि के 15% भाग को पहले की स्थिति में लाने में कामयाब हो जाएं, तो प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे में 60% की कमी आ जाएगी। यदि हमें वैश्विक तापन को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, बढ़ती आबादी को खाद्य सुरक्षा देनी है और पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों को नष्ट होने से बचाना है तो विश्व के सभी देशों को सौ करोड़ हेक्टेयर नष्ट हुई कृषि एवं वन भूमि को पुनः पूर्वस्थिति में लाने के अपने वादे पर अमल करना चाहिए। और इसी प्रकार का संकल्प समुद्री और समुद्र तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के विषय में भी करना चाहिए। दरअसल आज स्थिति यह है कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए विकसित देशों को जितना खर्च करना है, उतना वे खर्च नहीं कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भी बच रहे हैं। यूएनईपी की रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि अपेक्षित व्यय और वास्तविक व्यय का यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। विकासशील देश बिना विकसित देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आर्थिक एवं तकनीकी सहायता के अपनी विकास प्रक्रिया को प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण हितैषी नहीं बना सकते।

सपंर्क करें:

अलका पाण्डेय

हाउस नं.-70, बड़ी बाग कॉलोनी,
निकट मजार, लंका मैदान, गाजीपुर,
पिन-233 001 (उ.प्र.)
मो. 6265083116